भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3311

जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2023 को दिया जाना है।

18 श्रावण, 1945 (शक)

पीएम- दिशा

3311. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:
श्री अरविंद धर्मापुरीः

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2017 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएम-दिशा) के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना में केवल 9.36 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया है और 9.32 लाख छात्रों ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षित छात्रों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पीएम-दिशा (पीएमजीडीआईएसएचए) के बारे में और अधिक जागरूकता बढ़ाने तथा इसमें पंजीकृत और प्रशिक्षित छात्रों की संख्या में वृद्धि करने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य में 9.36 लाख छात्रों में से केवल 5.53 लाख छात्रों को ही वास्तव में प्रमाणित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) सरकार इस योजना की समस्याओं का किस प्रकार समाधान कर रही है;

(च) क्या सरकार ने पीएम-दिशा (पीएमजीडीआईएसएचए) के वास्तविक कार्यकरण के संबंध में कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(छ) इस योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक, इसके अंतर्गत डिजिटल साक्षर के रूप में प्रमाणित लोगों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ज) पीएम-दिशा योजना के अंतर्गत विशेषकर निजामाबाद में जिला-वार प्रमाणीकरण और नामांकनों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) से (ङ) और (छ) : पिछले 9 वर्षों में भारत अपने नागरिकों के लाभ और उनके जीवन में बदलाव के लिए प्रौद्योगिकियों को नियोजित करने में एक प्रमुख राष्ट्र बन गया है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार देश भर में, खासकर ग्रामीण इलाकों में नागरिकों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अनुरूप देश भर में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) को शामिल करने के लक्ष्य के साथ ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता की शुरुआत करने के लिए फरवरी 2017 में प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) शुरू किया गया था। अब तक कुल 7.04 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों को नामांकित किया गया है और 6.08 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 4.53 करोड़ उम्मीदवारों को देश भर में पीएमजीदिशा योजना के तहत प्रमाणित किया गया है। राज्य /संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति **अनुबंध I** में दी गई है।

आंध्र प्रदेश राज्य में अब तक 20.85 लाख से अधिक उम्मीदवारों को नामांकित किया गया है और 17.09 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। इनमें से लगभग 12.20 लाख उम्मीदवारों को विधिवत

प्रमाणित किया जा चुका है। इसके अलावा तेलंगाना राज्य में, अब तक 12.72 लाख से अधिक उम्मीदवारों को नामांकित किया गया है और 10.36 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। इनमें से लगभग 7.19 लाख उम्मीदवारों को विधिवत प्रमाणित किया जा चुका है।

पीएमजीदिशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य सहित पंजीकृत और प्रशिक्षित छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदम इस प्रकार हैं:

i. अभियानों, कार्यशालाओं, सेमिनारों, डिजिटल वैन आदि के माध्यम से डिजिटल साक्षरता के प्रति जागरूकता और प्रचार गतिविधियों को बढ़ाना।

ii. ग्रामीण आबादी वाले जिलों को शामिल करने के लिए कुछ ग्रामीण स्कूलों को उम्मीदवारों के प्रशिक्षण और जांच के लिए लगाया गया है ।

iii. इच्छित लाभार्थियों तक योजना के संबंध में जानकारी प्रसारित करने के लिए विभिन्न तंत्र अपनाए गए हैं जैसे मौखिक प्रचार, ऑनलाइन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें पोस्टर, बैनर, रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविजन, सोशल मीडिया आदि शामिल हैं।

iv. प्रशिक्षण सामग्री ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर उपलब्ध कराई गई है।

(च) :पीएमजीदिशा योजना का मूल्यांकन अब तक तीन एजेंसियों अर्थात् आईआईटी दिल्ली, सामाजिक विकास परिषद (सीएसडी) और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा किया गया है। पीएमजीदिशा योजना का अंतिम प्रभाव आकलन अध्ययन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा आयोजित किया गया है। पीएमजीदिशा योजना की आईआईपीए प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के निष्कर्ष **अनुबंध- II** में दिए गए हैं ।

(ज) : पीएमजीदिशा योजना के तहत तेलंगाना के निज़ामाबाद जिले में, अब तक कुल 33,987 उम्मीदवारों को नामांकित किया गया है और 14,095 उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है। जिलेवार स्थिति https://www.pmgdisha.in/students-count-list/ पर देखी जा सकती है।

****

अनुबंध 1

पीएमजीदिशा योजना की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत	प्रशिक्षित	प्रमाणित
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5,239	2,678	1,659
2	आंध्र प्रदेश	20,91,197	17,12,425	12,23,024
3	अरुणाचल प्रदेश	8,471	5,856	3,908
4	असम	27,07,602	23,47,991	18,65,471
5	बिहार	78,54,384	70,19,986	51,48,492
6	छत्तीसगढ	25,04,227	21,55,181	16,29,755
7	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	15,734	12,374	8,974
8	गोवा	58,569	53,784	40,000
9	गुजरात	29,03,805	25,54,363	18,83,647
10	हरियाणा	18,70,129	15,89,082	11,91,000
11	हिमाचल प्रदेश	5,61,694	4,36,559	3,22,191
12	जम्मू और कश्मीर	7,93,086	6,31,090	4,57,982
13	झारखंड	26,63,483	22,03,542	16,25,477
14	कर्नाटक	18,92,972	13,95,262	9,63,279
15	केरल	91,798	44,634	32,829
16	लक्षद्वीप	142	35	0
17	मध्य प्रदेश	57,27,927	51,00,915	37,84,166
18	महाराष्ट्र	58,83,985	50,68,867	36,61,594
19	मणिपुर	26,615	17,063	11,067
20	मेघालय	1,48,977	1,03,279	69,360
21	मिजोरम	28,648	21,479	13,339
22	नगालैंड	9,872	6,149	4,247
23	ओडिशा	35,34,929	29,99,545	22,73,614
24	पुदुचेरी	22,002	15,861	11,068
25	पंजाब	17,37,888	15,07,613	11,60,647
26	राजस्थान	41,93,428	36,52,200	26,74,858
27	सिक्किम	25,842	22,166	16,233
28	तमिलनाडु	15,87,621	12,91,356	9,57,627
29	तेलंगाना	12,75,226	10,37,527	7,19,891
30	त्रिपुरा	3,16,201	2,45,479	1,95,000
31	उत्तराखंड	7,88,200	6,75,131	5,06,000
32	उत्तर प्रदेश	1,64,46,000	1,46,65,463	1,11,10,632
33	पश्चिम बंगाल	26,67,740	22,31,783	17,41,160
34	लद्दाख	24,785	22,082	17,357
	कुल	**7,04,68,418**	**6,08,48,800**	**4,53,25,548**

***चंडीगढ़ और दिल्ली शहरी समूह में हैं, इसलिए इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।**

****

पीएमजीदिशा योजना : आईआईपीए प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

- पीएमजीदिशा अपने व्यापक पैमाने और दूर से संचालित परीक्षा के उपयोग के कारण एक अनूठी योजना है।
- एससीएसपी में 18%, टीएसपी के लिए 12% और एनईआर के लिए 11% फंड का उपयोग कर कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण सुनिश्चित किया गया है।
- महिलाओं की भागीदारी बहुत बड़ी है और ग्रामीण स्तर पर उनके शामिल होने से पूरे परिवार के लिए सीखने का रास्ता खुलेगा।
- 55% से अधिक उत्तरदाताओं ने पीएमजीदिशा प्रशिक्षण के बाद अपनी आजीविका में प्रत्यक्ष लाभ का दावा किया।
- लगभग 50% उत्तरदाताओं ने कहा कि पीएमजीदिशा ने उन्हें बेहतर नौकरी पाने में मदद की।
- 40% से अधिक उत्तरदाताओं ने 1-5 लोगों को सशक्त बनाया, 22.8% 6-10 लोगों की मदद करने में सक्षम थे, 12.9% पीएमजीदिशा के ज्ञान से 10-20 लोगों की मदद करने में सक्षम थे।
- पीएमजीदिशा प्रशिक्षण का आईसीटी और डिजिटल मीडिया के अन्य रूपों के उपयोग पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है।
- पीएमजीदिशा ने कई उद्देश्यों के लिए सूचना बिंदुओं और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक उनकी पहुंच को सुविधाजनक बनाकर लाभार्थियों की सेवा की है। इससे देश में समग्र डिजिटल विभाजन को कम करने में मदद मिली है।
- कोविड 19 ने ग्रामीण भारत में भी अनिश्चितता की अभूतपूर्व स्थिति पैदा कर दी है। पूर्ण लॉकडाउन के समय में भी डिजिटल पहल ने बहुत सी चीजों को कार्यशील बना दिया है। ऑनलाइन प्रक्रियाओं की उपलब्धता के कारण बैंकिंग प्रणालियों से लेकर ई-गवर्नेंस प्रणालियों और पीडीएस को काफी मदद मिली। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने डिजिटल प्रणालियों की मदद से अपनी आजीविका जारी रखी है, जिससे उनकी उपज की खरीद, घर तक वित्तीय सेवाएं, सूचना एकत्र करना और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना अन्य चीजों में मदद मिलती है। नए परिवेश में ऐसे आदर्श बदलाव के समय में पीएमजीदिशा जैसे कार्यक्रमों की आवश्यकता एक जरूरत बन गई है। डिजिटल टूल और आईसीटी को समझना और उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करना समय की मांग है और यह आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के समर्थन में मौजूदा संकट के लिए रक्षक साबित हुआ है।

****